वर्ष : 31 अंक : 6 नवम्बर – दिसम्बर 2008

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

ABVP

छात्र शक्ति की है ललकार, घुसपैठिये भेजो सीमा पा

ABVP Declares
War Against
Bangladeshi
Infiltration

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 31 अंक : 6 ● नवम्बर–दिसम्बर 2008

संरक्षक
अतुल कोठारी

संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल

प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011 – 23093238 , 27662477
E-mail : chhathrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

12 जनवरी
विवेकानंद जयंति

विषय सूची

7 बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध छात्र आन्दोलन

10 घुसपैठ नहीं यह हमला है

13 बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ नये जन आंदोलन का संकेत

15 मुम्बई हमलों के निहितार्थ

19 शैक्षिक परिवर्तन : आगामी दिशा एवं योजना

23 **India offers great opportunity**

25 **Career**

मुलाकात

प्रा. मिलिंद मराठे – राष्ट्रीय अध्यक्ष अभाविप.....17

परिचर्चा

पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर अमेरिका हमला कर सकता है तो भारत क्यों नहीं ?.....21

परिषद् गतिविधियां.....27

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

Prof.Milind Marathe and Shri Vishnu Dutt Sharma is New National President and General Secretary

- Prof. Milind Marathe -

- Vishnu Dutt Sharma -

Prof. Milind Marathe (Thane, Maharashtra) and Shri Vishnu Dutt Sharma (Bhopal, Madhya Pradesh) has elected as National President and General Secretary respectively of ABVP, Premier student organisation of the nation.

It is announced by Dr.Durga Prasad Agarwal (Election Officer) at Central office of ABVP.The term of office of both the newly elected office bearers will remain for one year. They will take charge of their post in 54 National Conference of ABVP scheduled on 23rd January, 2009 at Jalgaon (Maharashtra).

Prof. Milind Marathe M.E. (Electrical) from VJTI, is working as Asst. Professor with K. J. Somaiya Engg. College, Mumbai. He is also known for deep study about Higher Educational Policies & being active since 1979 with ABVP. He has presented various papers on Education at different national seminars. He has also visited Afghanistan as member of Indian Voluntary Organisation 'Goodwill Mission' in May, 2002. Till the date he held various responsibilities of ABVP as state organising secretary Rajasthan, President - Maharashtra state etc. and from 2004 to 2008 he was National Vice President.

Shri. Vishnu Dutt Sharma is basically from Muraina Dist., Madhya Pradesh and being active since 1981 with ABVP. From 1995 he is working as a full time worker of ABVP after passing his M.Sc. (Agriculture) .Till the date he has held various responsibilities like Vibhag organising secretary, State secretary, State organising secretary, Zonal organising secretary etc. and he was also remain National Secretary from 2003 to 2006.He has successfully led so many national & state level agitations organised by ABVP,he has also played significant role on national level especially in Madhya Pradesh in agitations against Commercialisation and Corruption in education organised by ABVP .

राष्ट्रवाद व लोकतंत्र की जय

हाल ही में कुछ अच्छी प्रवृत्तियां उभरकर सामने आई हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू–कश्मीर और बंगलादेश में भारी संख्या में लोगों ने 'लोकतंत्र पर्व' में सहभागी होकर अलोकतांत्रिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ओर जहां हमारे देश के अभिन्न राज्य जम्मू–कश्मीर में जनता ने अलगाववादी ताकतों को सबक सिखाया, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी बंगलादेश में लोकतंत्र का परचम बुलंद हुआ। जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रवादी दलों का तना व अलगाववादी ताकतों का परास्त होना तथा बंगलादेश में बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी व सेना समर्थित आपातशासन का खात्मा, भारत के लिए शुभ संकेत है।

बंगलादेश में दो साल सैनिक शासन सहित सात साल बाद संपन्न हुए आम चुनावों में अवामी लीग की नेता व पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना की शानदार जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन श्रीमती हसीना की राह आसान नहीं है। गौरतलब है कि बंगलादेश जहां आर्थिक बदहाली से जूझ रहा हैं वहीं आतंकवादी ताकतें भी यहां अपना अड्डा बनाये हुए हैं। भारत ने अवामी लीग को हमेशा ही मित्र माना है। इसलिए यह आशा करनी चाहिए कि नए नेतृत्व में बंगलादेश के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते सुधरेंगे।

आज दक्षिण एशिया में आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती हैं और इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि बंगलादेश आतंकवाद की शरण–स्थली बना हुआ हैं। हालांकि श्रीमती हसीना ने दक्षिण एशिया में आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रस्तावित साझा कार्यबल के बारे में कहा कि "इससे क्षेत्र के देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर आरोप–प्रत्यारोप का दौर खत्म होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि "जब हम सत्ता में थे, तब हमने कभी भी बंगलादेश की जमीन का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए होने नहीं दिया। हमारी हमेशा से पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की नीति रही है।" सुविदित है कि भारत में हुए कई आतंकी हमलों में बंगलादेश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के हाथ रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बंगलादेश अपने देश में आतंकवादी अड्डे को ध्वस्त करे। और यह तभी संभव हो सकेगा जब वहां एक सशक्त लोकतंत्र कायम हो।

जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय लोकतंत्र व राष्ट्रवाद की जीत हुई। खराब मौसम के बावजूद लोगों ने भारी संख्या में मतदान कर अलगाववादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। राज्य की जनता ने साफ संदेश दिया कि वोट बैंक की आड़ में राष्ट्रीय हितों से समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चुनाव में सबसे अधिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ और उसकी सीटें एक से ग्यारह हो गई वहीं अलगाववादियों की सुर में सुर मिलाने वाली पीडीपी को झटका लगा और वह सत्ता प्राप्त करने से दूर रही। अब समय आ गया है कि हुर्रियत समेत तमाम अलगाववादी संगठनों को आत्मावलोकन करना चाहिए। विदित हो कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दिए जाने के मसले पर पीडीपी ने जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था पर चोट की, इसका सबक उसे जम्मू के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में सिखा दिया। अमरनाथ आंदोलन से न केवल जम्मू वरन् पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई।

जम्मू–कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है। राज्य के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री उमर अबदुल्ला को अपने रुख में परिवर्तन लाना होगा। ध्यातव्य है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान उन्होंने हिन्दुओं को एक इंच जमीन न देने का ऐलान किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में केवल कश्मीर को ध्यान में रखकर ही सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और जम्मू व लद्दाख क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। देश की आजादी के बाद से ही जम्मू–कश्मीर में अलगाववाद एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकार शासन को गतिशील करे कि जम्मू–कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीयता का रंग चढ़े। ■

Good Morning, India

– Akankasha Sharma –

The aftermath of the 26/11 terror attacks in Mumbai, is that India has once again awakened to reality. The youth that once only paid attention to the amorous SRK, the stunning tinsel town beauties, and the picturesque locales in Hindi Movies, has now roused to the real-time (actual) Indian scenario. And, it's about time, too.

I remember how I myself sat in a limbo before the television set, watching every bit of the defensive attack launched by the NSG, as their commandoes descended from the sky onto the roof of Nariman House. I remember checking the highlights again and again for confirmation from the NSG Chief, that the renegades had been captured or killed, and Mumbai was safe again…

Night after night, India watched as the world slept, what transpired once the terrorists were appeased. India was screaming, moaning in pain, crying for its martyrs, crying for its sons, crying for its daughters, and for everyone that hadn't previously been mourned before.

For days on end, India cried for its most brave children, and it raged against the powers of this mighty country, questioning them why they couldn't have been saved, why were there so many families marred forever with the scar that no gifted plastic-surgeon could hide…

Life in the country moved on, but so did the dawn of realization increasingly grips its sleepy state, and threw open naked the weaknesses of the defenses in the nation's commercial capital.

Across the news channels, the general public asked for answers to questions that had never found voices. The common man cried for justice from the men, on whom they had vested the power to grant it. The country displayed its resilience and its resistance to the world with the city lawyers publicly turning down and refusing to obey any orders to represent a terrorist.

The nation saluted its heroes, because for the first time since the coverage of the 1999 Kargil War against Pakistan, had they seen a battle as it happened on the battlegrounds live in their homes. They heard real gun shots, saw the valor of the Chiefs of the Nation's forces don a bullet-proof jacket, as it marveled and brimmed with pride at their ease of going about the ritual before the dance of death commenced; unperturbed by the thought that they would probably never come back. Such is the feat of the immortal martyr, as tragic and as eternal as an end can get. And after this mournful juncture, I would like to greet the nation a very good morning…

Good Morning India, say good morning to your brand-new conscious days, to the no more lethargic nights… good morning India, say good morning to your neighbors because you still get to do so, because the martyrs can't, because you exist and they don't… Good morning, India, to the new dawn of the sun-kissed city beaches, a night after they died. Good morning, India, to the view of the world when it views you; to your realization of your weaknesses, as you enjoyed your strengths, as you now vow to eliminate your Achilles' heel.

Good morning India, to the endless struggle 'for freedom' in the North and in the East. Good morning India, good morning to the food you eat….good morning India, to the breath you take.

Good morning, India, to the nation's new day, its new awakening, its new life, and its new beginning… ■

बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध छात्र आन्दोलन

– आशुतोष भटनागर –

रैली छात्रों की थी । उनके बीच एक वृद्ध महिला की उपस्थिति चौंकाने वाली थी। आप यहां क्यों आयी इस सवाल पर टूटी–फूटी स्थानीय भाषा में उसने जवाब दिया– मैं नहीं जानती कि यह लोग कौन हैं, लेकिन पहली बार कोई हमारी बात बोल रहा है, इसलिये मैं यहां बैठी हूं। प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिये गया तो कार्यालय के बाहर ही एक बुजुर्ग आदमी ने स्थानीय आयोजकों में से एक श्री जायसवाल के पांव पकड़ लिये। भावुकता में उनके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह सिर्फ दोहरा रहे थे– आप तो हमारे लिये भगवान हैं। आप नहीं होते तो किशनगंज में हमारी बात उठाने के लिये कोई नहीं आता।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के आह्वान पर बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बिहार के किशनगंज में यह रैली आयोजित की गयी थी। मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से शुरू हुई रैली को सम्बोधित करते हुए छात्र नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से निकाल बाहर करने की पुरजोर मांग की ।

संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अम्बेकर ने कहा कि बांग्लादेश आज पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की सहयोग भूमि बन गया है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में विश्व समुदाय को केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में जारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति भी कड़ा रुख अपनाना होगा । महामंत्री सुरेश भट्ट ने राज्य व केन्द्र सरकारों को चेताते हुए कहा कि उन्होंने नाकारापन न छोड़ा तो उन्हें भी नहीं बख्शा जायेगा। रैली संयोजक सुनील बंसल ने रैली को जिहादियों के खिलाफ जिहाद बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रामनरेश सिंह ने राजनैतिक सत्तालोलुप नेताओं की खामोशी को चुनौती देते हुए परिषद कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों और विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने का संकल्प दिलाया।

स्थानीय नागरिकों में से कुछ लोग इस आशंका से भी सहमे दिखे कि घुसपैठियों के खिलाफ बोल कर यह लोग तो चले जायेंगे लेकिन बाद में घुसपैठिये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। नाम न देने के आग्रह के साथ अनेक लोगों ने कहा कि प्रशासन भी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता है जिसके कारण वे बेखौफ अवैध गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं।

किशनगंज के जिलाधिकारी फेराक अहमद से जब घुसपैठियों की संख्या की बाबत सवाल किया तो उन्होंने दो टूक उत्तर दिया– किशनगंज जिले में एक भी घुसपैठिया नहीं है। उनका मानना था कि किशनगंज एक शांतिपूर्ण जिला है जहां घुसपैठ कोई समस्या नहीं है।

रेलवे स्टेशन पर मोहम्मद शमीम आलम से मुलाकात हो गयी। उनसे मिलने से पहले तक समझ यही थी कि

घुसपैठ के कारण जिले में अल्पसख्यक हिन्दुओं (किशनगंज मे हिन्दुओं की जनसंख्या केवल 24 प्रतिशत रह गयी है) को कष्ट उठाना पड़ता है। किन्तु शमीम ने बताया कि शताब्दियों से यहां रह रहे मुस्लिमो को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। इन घुसपैठियों में जबरदस्त एकता है और किसी भी विवादकी स्थिति में वे तुरंत इकट्ठे हो जाते है। वे उनके सामाजिक ताने–बाने को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके रोजगार भी हड़प रहे हैं।

जनसांख्यिक परिवर्तन द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से अलग कर बांग्लादेश में जोड़ने के मंसूबे छिपे नहीं हैं। 1971 में असम मे हिन्दू जनसंख्या 94.5 प्रतिशत और मुस्लिम जन संख्या 5 प्रतिशत थी। 2005 में यह अनुपात बदल कर क्रमशः 63.5 और 33 प्रतिशत(अनुमानित) हो गया है। 2001 की जनगणना के समय यह 65.4 तथा 30.9 प्रतिशत था। 2004–5 के एक वर्ष में ही असम की मतदाता सूची में 21,76,549 नये नाम जोड़े गये। यह वृद्धि 14. 52 प्रतिशत है। असम के 46 और पश्चिम बंगाल के 52

विधानसभा क्षेत्रों में इन घुसपैठियों की निर्णायक भूमिका है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी मुस्लिम जनसख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

वोट बैंक की राजनीति और भ्रष्टाचार के चलते इन घुसपैठियों को भारत में राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र बनवाने में कोई कठिनाई नहीं होती। घुसपैठ से सर्वाधिक प्रभावित असम में घुसपैठियों की पहचान और उनको वापस भेजने की प्रकिया आई एम डीटी एक्ट के तहत कितनी जटिल थी इसका अनुमान इस तथ्य से मिलता है कि 1983 से 2005 के बीच 22 वर्षों में कुल 2,10, 759 दर्ज मामलों में से केवल 10,015 को ही विदेशी नागरिक घोषित किया जा सका। इनमें से भी केवल 1467 को ही वापस भेजा जा सका। इस प्रक्रिया पर 300 करोड़ रुपये खर्च हुए अर्थात प्रत्येक घुसपैठिये की पहचान कर उसे निकालने का खर्च 24,59,808 रुपये।

रैली में सरकार से भारत बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी पूरी करने, लड लाइट और सर्च टॉवर स्थापित करने, सीमा

सुरक्षा बल को व्यापक अधिकार प्रदान करने, सीमा रेखा पर हाल ही में बनाये गये मस्जिद एवं मदरसों पर नजर रखने, अवैध निर्माणों को हटाने, 1951 को आधार मान कर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने, उनका नाम मतदाता सूची से हटाने तथा नागरिकता समाप्त कर वापस भेजने, इसके लिये स्वतंत्र टास्क फोर्स बनाने, घुसपैठ संबंधी सुनवाई के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन, सीमा पर नये बसे गांवों की जांच, सीमावर्ती क्षेत्र हेतु विशेष विकास योजना, दूरसंचार व यातायात सुविधाओं के विकास, बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गयी लाखों एकड़ वन, सत्र व सरकारी भूमि को मुक्त कराने, आतंकवादी व कट्टरपंथी गुटों पर नकेल कसने तथा चिकन नेक पट्टी को स्पेशल प्रोटेक्शन जोन घोषित करने की मांग की गयी ।

भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग है 32 किलोमीटर लम्बी और 18 से 24 किलोमीटर चौड़ी चिकननेक पट्टी। इस पट्टी पर ही पश्चिम बंगाल के दालकोला से भोलामारी तक उत्तरपूर्व रेलवे का रेलमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 साथ–साथ चलते हैं। यदि यह मार्ग बाधित कर दिया जाय तो पूर्वोत्तर का शेष भारत से संपर्क समाप्त हो सकता है।

सुरक्षा की दृष्टि से यह पट्टी देश का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन, नेपाल और बांग्लादेश की

सरहदें यहां से नजदीक हैं। यह पट्टी भी प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बंटी है। एक हिस्सा बिहार के किशनगंज जिले मे पड़ता है तो दूसरा भाग प.बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में है। चिकन नेक पट्टी के रक्षा महत्व पर चीन के आकमण

के समय से ही चर्चा होती रही है लेकिन आज तक न तो राज्यों ने और न ही केन्द्र ने इसकी सुरक्षा की कोई ठोस योजना बनायी । नतीजा है कि सरकारी बयानबाजी के बावजूद इस पट्टी पर घुसपैठियों की जनसंख्या 90 प्रतिशत तक हो गयी है।

यह विचित्र तथ्य है कि विभिन्न छात्र संगठन इस समस्या की ओर पिछले तीन दशकों से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं किन्तु सरकार, जिसकी यह जिम्मेदारी है,के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आसाम में इसके विरुद्ध एक बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। सरकारें बार–बार बदलती रहीं पर समस्या बढ़ती ही गयी।

1977 के लोकसभा चुनाव के समय मतदाता सूचियों में 45 हजार विदेशी नागरिकों के नाम जोडे गये तो आम जनता ने इसका जोरदार विरोध किया। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के नेतृत्व में व्यापक जन आन्दोलन प्रारंभ हुआ । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस आन्दोलन को पूरे देश में पहुंचाया।

इस बीच आसू के नेताओं ने असम गण परिषद के नाम से चुनाव जीत कर सत्ता भी संभाली लेकिन उनकी आंदोलनपरता पर राजनैतिक बाध्यताएं हावी हो गयीं । असम की जनता को निराश होना पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बताते हुए बार–बार चेताया किन्तु राजनीति के बहरेपन के सामने उसका आंदोलन भैंस के आगे बीन बजाना ही साबित हुआ।

इन तीन दशकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लाखों से बढ़कर करोड़ों में पहुंच चुकी है। सीमावर्ती जिलों से आगे बढ़कर देश की राजधानी सहित पूरे भारत में उनकी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। आई एस आई और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उनके गठजोड़ के सबूत मिल रहे है। छोटे–मोटे अपराधों से लेकर जाली नोटों, हथियारों, मादक पदार्थों तथा पशुओं की तस्करी तक में उनकी भागीदारी जगजाहिर है।

गत एक वर्ष में हुई प्रायः प्रत्येक आतंकवादी घटना के सूत्र बांग्लादश से जुड़ने के बाद अभाविप ने एक बार फिर अपने तीन दशक पुराने आंदोलन को गरमाते हुए चिकन नेक पट्टी से जुड़े बिहार के किशनगंज में विशाल राष्ट्रीय प्रदर्शन एवं रैली का आयोजन किया। देश भर से तीस हजार से ज्यादा छात्र–नौजवान इस रैली में जुटे। किशनगंज में जिस समय यह रैली जारी थी समान्तर रूप से देश भर में इसी मुद्दे पर धरनों की श्रंखला भी जारी थी। सुनील बंसल के अनुसार लगभग दो सौ जगहों पर एक ही समय हुए इन धरनों में पचास हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।

घुसपैठ नहीं यह हमला है

चिकननेक में विद्यार्थी परिषद् की विशाल छात्र रैली

17 दिसम्बर को किशनगंज (बिहार) के रूईधासा मैदान में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने विशाल सभा एवं रैली आयोजित की। जिसमें **'चलो चिकननेक'** की हुंकार के साथ पूरे देश से 30 हजार से अधिक छात्र–छात्रायें एवं 10 हजार से अधिक स्थानीय जनता ने भाग लिया।

– सुनील बंसल –

(राष्ट्रीय संयोजक
बंगलादेशी घुसपैठ विरोधी आंदोलन समिति)

देशभर से आई तरूणाई अपने हाथों में तिरंगा झण्डा लेकर "किशनगंज हो या गोहाटी–अपना देश अपनी माटी", "घुसपैठ नहीं यह हमला है, घुसपैठियें भगाओ–देश बचाओ" जैसे नारे लगाते हुए रूईधासा मैदान पहुंचे। तीन अलग–अलग स्थानों से ये रैलियां प्रारम्भ हुई। इन रैलियों का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रामनरेश सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री सुरश भट्ट, आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक सुनील बंसल ने किया।

ये रैलियां शहर के प्रमुख मार्गो से जब निकली तो स्थानीय किशनगंज की जनता में उत्साह का महौल था। शहर के विभिन्न भागो में स्वागत के लिए तोरण द्वार तथा पुष्प वर्षा से छात्रशक्ति का उत्साहवर्धन किया गया। अनुशासित एवं देशभक्ति पूर्ण वातावरण के साथ पूरा शहर भगवामय दिखाई दे रहा था। रूईधासा मैदान में रैली के बाद सभा आयोजित की गई।

यह सभा मुम्बई हमलो में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजली देकर प्रारम्भ हुई। सभा में विशाल मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रामनरश सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आम्बेकर, सहसंगठन मंत्री श्री बी सुरेन्द्रन, घुसपैठ विरोधी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री सुनील बंसल, सभी राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.मिलिन्द मराठे, प्र जयकुमार तथा सभी प्रान्तों के प्रान्त मंत्री उपस्थित थे। सभा के प्रारम्भ व अन्त में हैदराबाद के प्रेरणा समूह के युवाओं ने देश भक्ति गीत प्रस्तुत किए।

सभा को सम्बोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रामनरेश सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन देश के राजनैतिक सत्तालोलुप नेताओं के विरूद्ध भी खुली चुनौती है जो वोट बैंक की राजनीति के कारण खामोश बैठे है। हम भारत की एकता एवं अखण्डता के साथ किसी भी प्रकार के समझौते को गलत मानते है और अपनी पूरी शक्ति के साथ ऐसे समझौते करने वाले राष्ट्रविरोधियों व अलगाववादी मानसिकता के आधार पर आतंकवाद फैलाने वाले व घुसपैठियों के माध्यम से विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने का दृढ़ संकल्प लेते है।

राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरे श भट्ट ने कहा कि घुसपैठ समस्या कोई सुनामी नहीं है जिसका हम यह कह कर छुटकारा नही पा सकते कि हमें मालूम नही था, यह अचानक हो गया। यह समस्या पिछले 30 वर्षों से लगातार हो रही है। जिसे लेकर केन्द्र व राज्य सरकार खामोश है। उन्होने असम के मूल निवासी घुसपैठ बहुल्य क्षेत्रों की चर्चा करते हुए कहा कि आज असम के मूल निवासी अपने को सुरक्षित

महसूस नहीं कर रहे है, सरकार द्वारा असमवासियों के लिए दिए जा रहे आर्थिक पैकेज का एक बड़ा हिस्सा इन घुसपैठियों के हिस्से में जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए हम खून दे सकते है तो विश्व के नक्शे से उसे मिटाने के लिए भी हम कोई कसर नही छोड़ेगें।

विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठनमंत्री श्री सुनील आम्बेकर ने कहा कि 1971 में जो बांग्लादश मित्र राष्ट्र था वहीं आज भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। वर्तमान बांग्लादेश निश्चित रूप में पाकिस्ताान में सक्रिय आंतकी संगठनों की सहयोग भूमि बन गया है। जहम आंतकवाद की बात कर रहे है तो हमें विश्व समुदाय को केवल पाकिस्ताान नहीं अपितु बांग्लादेश की गतिविधियों को भी गंभीरता से लेते हुए बांग्लादेश के प्रति कड़ा रूख अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश पुनः पूर्वी पाकिस्ताान बनने जा रहा है।

बांग्लादेश घुसपैठ विरोधी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री सुनील बंसल ने कहा कि बांग्लादेश से भारत में लगभग 3 करोड़ घुसपैठिये आ चुके है और ये लोग भारत के कोने–कोने में फैले हुए है। विद्यार्थी परिषद ने आज तक देश के कोने–कोने में जहां भी कहीं राष्ट्रीय संकट गहराया है तो जंतर–मंतर पर सांकेतिक धरने नहीं दिए बल्कि वही जाकर आंदोलन किया है, जहां समस्या रही है। चाहे कश्मीर की समस्या हो चाहे असम की, आंतकवाद हो या नक्सलवाद हो, तीन बीधा हो या चिकननेक हमने इसे किसी विशेष क्षेत्र की समस्या नहीं अपितु राष्ट्रीय समस्या माना और राष्ट्रीय आंदोलन खड़े किए है।

सभा को परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्री जी लक्ष्मण (हैदराबाद), श्री श्रीनिवास (रोहतक), सुश्री आशा लकड़ा (रॉची), श्री संदीप कुमार (चैन्नई) तथा सिद्धो कानू मूर्मु विश्वविद्यालय झारखंड क छात्रसंघ अध्यक्ष श्री राजीव रंजन, JNU दिल्ली के छात्र डॉ मोहम्मद शमीम आलम, असम के प्रांत मंत्री श्री विश्वजित, पं.बंगाल के प्रांत सहमंत्री सुश्री पारूल मंडल, हिमाचल प्रदेश की छात्रनेता सुश्री मांचली ठाकुर, मध्य भारत की छात्रनेता सुश्री भारती एवं घुसपैठ आंदोलन के बिहार प्रांत संयोजक श्री शरद चंद्र संतोष ने उपस्थित छात्र शक्ति को आह्वान किया कि अगर सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने और रोकने के लिए पहल नहीं की तो देश की छात्र–शक्ति उसका मुंहतोड़ जवाब देगी।

इस अवसर पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि भारत–बांग्लादेश सीमा को पूरी तहर बंद किया जाए। सीमा सुरक्षा बल को व्यापक अधिकार दिए जाएं। घुसपैठ के संदर्भ में Detect, Delete & Deport की नीति अपनाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित मदरसों और मस्जिदों एवं अन्य धार्मिक स्थलों की जांच की जाए और यह भी मांग की गई कि घुसपैठियों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र 'टास्क फोर्स' बने।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख मा.श्रीकृष्ण मुतलग, सह बौध्दिक प्रमुख मा.दत्तात्रेय होसबाले, अ.भा कार्यकारी मण्डल के सदस्य मा.इन्द्रेश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बाल आप्टे, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित ठक्कर, पूर्व क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक श्री सुनील गोस्वामी, उत्तर–पूर्व क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक डॉ कृष्ण गोपाल, शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री अतुल कोठारी, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक श्री पी.वी.कृष्ण भट्ट सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ इस ऐतिहासिक रैली के समापन पर विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रामनरेश

सिंह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प सबको कराया। आंदोलन संयोजक श्री सुनील बंसल ने सभी को धन्यवाद दिया, सभा का संचालन राष्ट्रीय मंत्री समय बनसोड ने किया।

सभा के पश्चात किशनगंज के जिलाधिकारी श्री फैराक अहमद को राष्ट्रीय ध्वज व प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रामनरश सिंह के नेतृत्व में गये प्रतिनिधि मण्डल द्वारा सौपा गया।

पूर्व में देश भर के सभी प्रान्तो में रैली के लिए आने वाले छात्र–छात्राओं को वहां के स्थानीय लोगों और उनके माता–पिता ने तिलक लगाकर, आरती उतारकर सम्मानपूर्वक विदा किया। इन छात्रो को मार्ग के रेल्वे स्टेशनों पर अपूर्व स्वागत एवं भोजन–पानी की समूचित व्यवस्था स्थानीय जनता द्वारा की गई। कलकत्ता स्टेशन पर तो स्वागत एवं भोजन की विशेष व्यवस्था वहां के कार्यकर्ताओं ने की थी। देश भर से आ रहे इन छात्रों ने टिकट लेकर यात्रा की, इसका रेल्वे प्रशासन पर अच्छा प्रभाव रहने से उनका प्रशंसनीय सहयोग सभी जगह पर रहा।

16 दिसम्बर से ही यह छात्रशक्ति किशनगंज पहुंचने लग गई थी। स्थानीय गौशाला, स्टेडियम, जैन भवन में इन सभी की आवास व्यवस्था की गई थी। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था स्थानीय लोगों की मदद से की गई। लगभग 40 हजार भोजन पैकिट स्थानीय किशनगंज के लोगों ने अपने–अपने घरो से बनाकर भेजे। किशनगंज के आस–पास के घुसपैठ प्रभावित जनजाति क्षेत्र का विशेष सहयोग एवं सहभाग रहा। 500 जनजाति बंधु अपने तीर–कमान के साथ रैली एवं सभा की सुरक्षा कर रहे थे, 1500 से अधिक जनजाति बंधु एंव बहनें सभा में भी आयें।

16 दिसम्बर को देशभर से आये छात्र–छात्राओं ने बांग्लादेश सीमा की तरफ जाकर मानव श्रृंखला बनाई। जिसके माध्यम से बांग्लादेश की सरकार को घुसपैठ रोकने के लिए चेतावनी देने व केन्द्र सरकार अपना प्रतिनिधि छात्रो से वार्ता करने के लिए किशनगंज भेजने का संदेश दिया गया। इस मानव श्रृंखला का नेतृत्व राष्ट्रीय मंत्री सुश्री आशा लकड़ा ने किया।

जिस समय किशनगंज में सभा हो रही थी उसी समय देश के प्रमुख शहरो में धरने व प्रदर्शन आयोजित हो रहे थे। संसद के दोनों सदनों में भी यह मुद्दा उठाया गया। लोकसभा में श्री संतोष गंगवार व राज्यसभा में श्री जसवन्त सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठ का यह मुद्दा उठाकर सरकार से जवाब मांगा, परिणामस्वरूप गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने यह स्वीकार किया कि बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ हो रही है व हमे उधर से भी खतरा है।

इस रैली व सभा के कवरेज के लिए दिल्ली, पटना, सिलीगुडी, गोहाटी से काफी संख्या में पत्रकार पहुंचे। ETV व सहारा ने तो अलग से रिर्पोट बनाकर प्रसिद्धी दी।

घुसपैठ प्रभावित स्थानीय जनता मे इतना उत्साह था कि देशभर से आये इन छात्रो से रिक्श वाला पैसा नहीं ले रहा था, पान वाला, चाय वाले सभी इस प्रकार अपना समर्थन प्रकट कर रहे थे, उनको लग रहा था कोई तो है जो हमारी समस्या को लेकर यहां आवाज उठाने आया है।

किशनगंज में इस रैली के लिए व्यापक सम्पर्क अभियान चलाया गया। गांव–गांव, घर–घर जाकर कार्यकर्ताओं ने रैली में आने का आग्रह किया। महिला, बुद्धिजीवी, अल्पसंख्यक, राजनैतिक दल, प्रशासन के साथ सवांद, संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। जिससे स्थानीय जनता में व्यापक समर्थन देखने को मिला। ■

बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ नये जन आंदोलन का संकेत

– सुनील आम्बेकर –

(राष्ट्रीय संगठनमंत्री , अभाविप)

बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ दिनांक 17 दिसम्बर 2008 को अ. भा. विद्यार्थी परिषद् द्वारा घुसपैठ पीड़ित क्षेत्र 'चिकन नेक' के किशनगंज (बिहार) में देश भर से आए छात्रों का विशाल प्रदर्शन हुआ। लगभग छह माह से चल रहे चरणबद्ध आंदोलन ने समुचे देश में विशेष कर असम, पं.बंगाल, बिहार आदि घुसपैठ पीड़ित क्षेत्र में इस रैली के संदर्भ में काफी उत्सुकता बनी थी। इस रैली की सफलता ने नये व्यापक आंदोलन के संकेत दिये हैं। इसी की और संकेत करने वाला यह विश्लेशण–

असम में घुसपैठ विरोधी आंदोलन काफी पुराना है। 1979 से 1983 में ऑल असम स्टुडंट्स यूनियन (आसु) के नेतृत्व में यह अपनी चरम पर था व उसे आम जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था। आंदोलन के परिणाम स्परूप हुए असम समझौता से भी कई प्रश्न उत्पन्न हुए थे। वास्तव में 1947 में कश्मीर में हुए कबालीयों का हमला या 1998 में कारगील घुसकर किया गया कब्जा हो, असम में लाखों बांग्लादेशियों का अवैध रूप में घुसकर आना गंभीर उतना ही था। परन्तु सरकार तथा देश की जनता, मिडीया, आदि ने इस निःशब्द एवं निःशस्त्र आक्रमण की परिणामकारी शक्ति के आकलन में गलती की। अल्पसंख्यक मतों की राजनीति के दबाव में कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहीत हमारे अधिकांश तथाकथित सेक्युलर दलों ने देश पर हुए इस आक्रमण पर भी अपनी राजनीति जारी रखी। स्वाभाविक ही सरकारों का रवैया बांग्लादेशी घुसपैठ के सन्दर्भ में ढीलाढाला रहा, 'Low Profile' नीति चलती रही।

यह सराहनीय रहा है कि भारत विरोधी पाकिस्तान को 1971 के बांग्लादेश निर्मिती के हमारे योगदान ने कमजोर किया तथा बांग्लादेश जैसा एक पड़ोसी मित्र हमने पाया। परन्तु स्वप्न जल्द ही टूटा हम बांग्लादेश को पुनः पाकिस्तान की राह पर चलने से रोक नहीं पाए।

राजनैतिक नेतृत्व की घुसपैठियों के प्रति सौम्य नीति के विरोध का असम घुसपैठयों का आंदोलन एक पर्याय बन गया। परिणामस्वरूप आंदोलनकारी व केंद्र सरकार में ऐतिहासिक समझौता हुआ। परंतु घुसपैठियों पर कारवाई करने हेतु असम में विशेष कानून IM (DT) 1983 में लागू किया। परंतु इसके सारे प्रावधान घुसपैठियों के संरक्षण करने वाले थे। जनता ने आंदोलन के नेताओं को प्रदेश की सत्ता में बिठाया। परन्तु वह लोग भी कुछ ठोस कर नहीं पाये। आंदोलन कारी नेताओं की सरकार से मिली निराशा ने जनता में जगे आंदोलन के आवेश को कुछ हद तक थंडा किया तथा उसे काफी हद तक हताशा में बदल दिया था। दूसरी तरफ बिहार में श्री लालू यादव के राज में 15 वर्ष तक गुंडागर्दी, अफरातफरी एवं भ्रष्टाचार में घुसपैठियों को खूब संरक्षण मिला। पश्चिम बंगाल में कम्युनिष्ट सरकार ने हमेशा बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को ढाल बनाकर घुसपैठियों के खिलाफ कारवाई करने में छल किया। वहाँ जब भी आंदोलन प्रारंभ हुआ पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा की कम्युनिष्ट सरकार ने हिंदुओं को भारत छोड़ने के आदेश थमा देना प्रारंभ हो जाता है।

फिर कुछ बुद्धिजीवी गरीबी, रोजगार की तलाश एवं जनसंख्या के प्रकोप में समुह का पलायन आदि तर्क पर अप्रत्यक्ष रूप में घुसपैठ का समर्थन करते रहे। इन तर्क – वितर्क एवं वोट बॉक की ओछी राजनीति ने घुसपैठ की देशव्यापी व्यापकता तथा देश की सुरक्षा, एकात्मता व अखंडता के लिए खतरों को समुचे देश के सामने स्पष्ट रूप में लाने की जगह जनता को भ्रमित करने का काम किया है।

अ.भा.वि.प. की किशनगंज (बिहार) में घुसपैठ के विरोध में हुयी रैली, छात्रों का पुनः शंखनाद है नये जन आंदोलन का। जनता की हताशा को समाप्त करना बहुत आवश्यक था। देश की सुरक्षा, एकात्मता एवं अंखडता पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो छात्रों को जागृत करना जरूरी था। किशनगंज की रैली के निमित्त लगभग एक वर्ष से चले अभियान ने महाविद्यालयों में घुसपैठ के संकट के बारे में छात्रों काफी जागृत की। इसी का परिणाम था, कि कई महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के परिसर में सभाऐं हुई, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजे गए। देश के सभी जिलों में छात्रों ने विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में घुसपैठ के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। सभी जिला प्रशासन पर भी घुसपैठियों पर कार्यवाही हेतु दबाव देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप स्थानिक समाचार माध्यमों ने भी इस विषय की गंभीरता को भांपकर जन जागरण में काफी भूमिका निभाई है।

किशनगंज रैली पूरे देश में यह स्थापित कर दिया कि घुसपैठ केवल दो–चार प्रांतों की समस्या नहीं अपितु एक राष्ट्रीय संकट है। ऐसे राष्ट्रीय संकट के विरोध में केवल असम, बिहार तथा बंगाल नहीं अपितु पूरे देश को लड़ना होगा। इसी संकल्प के साथ किशनगंज में घुसपैठ के विरोध में सारे भारत भर से छात्र–छात्राऐं एकत्रित हुए थे। पूरे देश भर से आए छात्रों के संकल्प को शायद ही किसी ने कम आका होगा।

घुसपैठ प्रभावित क्षेत्र के लोग इस संकठ को रोज झेल रहे हैं, जैसे जमीन, पशु, संपत्ति आदि से लेकर घर में माँ–बहनों पर भी संकट। लेकिन सरकारों की निष्क्रियता, आछी वोट बैंक की राजनीति आदि ने उन्हें काफी निराश किया था, इस रैली के निमित्त काफी, वर्षों के बाद पुनः एक आशा लोगों के मन में जगी है। रैली के अंतिम दिनों में घुसपैठ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने दलगत राजनीति, जाति आदि से ऊपर उठकर इस आंदोलन का खुलकर सहयोग किया। यह कहना उचित होगा कि इस रैली ने घुसपैठ के विरोध में लोगों को संगठित एवं सक्रिय होकर आवाज बुलंद करने का मौका दिया।

घुसपैठ की सर्वाधिक कड़वी मार झेल रहे सीमावर्ती जिलों में जनजाति सामान्यतः मौन ही रह जाते हैं। परन्तु इस रैली को उन्होंने भी एक मौका माना, अपनी पीड़ा व आक्रोश व्यक्त करने का इसलिए बड़ी संख्या में सहभागी होने आए। बांग्लादश की सीमा पर चिकन नेक (किशनगंज) में राष्ट्रीय स्तर की रैली के कारण यह भी वहाँ के लोगों को लगा है कि हम अकेले नहीं, पूरा देश हमारा दुख समझ रहा है व संघर्ष में हमारे साथ खड़ा है।

छात्रों की सभा में समाज के सभी वर्गों की भारी उपस्थिति यह वास्तव में छात्रों के नेतृत्व में व्यापक जन आंदोलन का संकेत कर रही थी। पलायनवादी मानसिकता से इस रैली ने काफी हद हुए तक लोगों को बाहर निकाला है। उन्हें पुनः एक व्यापक संघर्ष के लिए तैयार किया है।

छात्रों के प्रतिनिधि मंडल का सामना करने की केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री हिम्मत तो नहीं जुटा पाये। परन्तु रैली के दिन संसद के दोनों सदनों में अर्थात लोकसभा में भाजपा के श्री संतोष गंगवार तथा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री जसवंत सिंह के द्वारा यह मुद्दा प्रभावी रूप में उठाया गया। सरकार की भी नींद थोड़ी टुटी है। रैली के बाद नये गृहमंत्री श्री चिंदबरम ने खुलकर अभाविप द्वारा उजागर तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है तथा छात्रों के आंदोलन को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की बात भी की है। परन्तु हो सकता है यह आनेवाले लोकसभा चुनाव देखकर किये गये दिखाई वक्तव्य हो। इसलिए लगातार आंदोलन का दबाव यह नितांत जरूरी है।

रैली ने कई स्थानीय आंदोलनों को जन्म दिया है। घुसपैठियें स्थानीय गरीब मजदूर, रिक्शा चालको के रोजगार या छोटे–मोटे दुकानदारों का व्यवसाय ही खींच रहे थे। घुसपैठियों पर दबाव बढ़ने से उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी। रैली के निमित्त गत कुछ महिनों से सतत रूप से जो अभियान चला उसने घुसपैठियों पर भी मानसिक दबाव बढ़ाया है जिसका संदेश सीमापार घुसपैठ के लिए तैयार लोगों तक भी पहुंचा है। अभाविप् के बांग्लादेशी घुसपैठ के विरूद्ध रैली को सांप्रदायिक बताकर घुसपैठियों का समर्थन करने का प्रयास भी हमेशा की तरह हमारे सेक्यूलरवादि गिरोह ने चलाया था। परन्तु इस रैली ने बांग्लादेशी घुसपैठ के विषय पर जनता का इतना व्यापक समर्थन पाया कि इनका दुश्प्रचार काम न आ सका व रैली शांतीपूर्ण तरीके से हुयी। इस सारे प्रकरण ने स्थानीय प्रशासन पर जरूर दबाव बढ़ाया है कि अब वह ठोस कारवाई प्रारंभ करें। अन्यथा उसे लोक क्षोभ का सामना करना होगा।

असम में आंदोलन हुआ, लगातार कई छोटे–छोटे स्थानीय आंदोलन होते रहे, अब देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हुआ है। छात्रों का दृढ़ संकल्प बनाना जरूरी है। अभाविप् ने देश की समूची छात्रशक्ति का आवाहन किया है कि आप हमारा साथ दो, तो हम सभी आजादी पायेंगे, घुसपैठियों से, असुरक्षा से। ■

मुम्बई हमलों के निहितार्थ

– आशीष कुमार 'अंशु' –

मुम्बई में हुए आतंकी हमले और 60 घंटे तक हुए संघर्ष को अब तक 60 दिन भी नहीं हुए हैं। जब आप यह लेख पढ़ रहे होंगे, हम इस सदी के सबसे बड़े हमले को भूला चुके होंगे। हो सकता है, थोडी बहूत बयानबाजी बची हो। अमरिका भारत को संयम से काम लेने की सलाह दे रहा हो और प्रदानमंत्री अमरिका के दबाव में खुद के ना होने के प्रति देश को आश्वस्त कर रहे होंगे। हो सकता है, पाकिस्तान के अदर भारत में अगले हमले की योजना बन रही हो। जैसाकि बताया जाता है, मुम्बई में आतकी हमले की जानकारी भारतीय सरकार के पास तकरीबन एक साल से थी। हो सकता है, आगे भी कुछ पाकिस्तानी कार्यवाहियों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के मार्फत से सरकार के पास हो लेकिन कार्यवाही की जगह हम बचाव की मुद्रा में है। वास्तव में यह एक धर्मनिरपेक्ष देश के धर्मनिरपेक्ष सरकार की नियति है।

पश्चिमी विद्वान मार्क सेजमेन ने जिहादी आतंकवादियों पर किए अध्ययन के हवाले से अपनी पुस्तक 'अंडरस्टैडिंग टेरर नेटवर्क' में लिखते हैं– '90 फीसदी आतंकवादी सुखी उच्च वर्ग अथवा उच्च मध्य वर्ग से आते हैं। इनमें 63 फीसदी आतंकी कॉलेज की पढ़ाई पढ़ चुके होते हैं। जबकि यह लोग जिन देशों से आते हैं (संकेत पाकिस्तान– अफगानिस्तान– बांग्लादेश सरीखे) वहां 5–6 फीसदी लोग ही कॉलेज की पढाई पढ़ पाते हैं। सेजमेन उदाहरण देते हैं, ओसामा बिन लादेन का जो पेशे से इंजीनियर है। मोहम्मद अता जो मनोवैज्ञानिक है और असमान अल जवाहिरी जो डॉक्टर है। सेजमेन के अनुसार पश्चिमी देशों पर हमला करने वाले तीन चौथाई आतंकी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक, कम्प्यूटर विशेषज्ञ हैं। लंदन में विफल हुए एक कार बिस्फोट में पकड़े गए आठ में से सात आतंकी डॉक्टर थे। इस तरह पाकिस्तान के विद्वान आरिफ एम अशरफ सरीखे लोगों का यह कहना कि पाकिस्तान में आतंकवाद की मूल वजह गरीबी और अज्ञानता है, बहूत हद तक सही प्रतित नहीं होती।

जैसाकि आप सब जानते हैं, 26 नवम्बर को देर रात पाकिस्तान पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, दो फाइव स्टार होटल ओबराय और ताज समेत आठ इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाकों के साथ अंधाधुन फायरिंग की। इस आतंकी हमले में पहले दिन मुम्बई पुलिस के डीआईजी अशोक कांते, और एटीएस चीफ हेमंत करकरे और विजय सालसकर शहीद हुए। आतंकियों के आने का रास्ता समुद्र

होकर बताया जाता है। भारत का समुद्री किनारा गुजरात के कांडला पोर्ट से होकर बंगाल के हल्दिया तक तकरीबन 7000 किलोमीटर में फैला हुआ है। समुद्र के ये किनारे एक तरफ बंगाल की खाड़ी से जा मिलते हैं और दूसरी तरफ अरब सागर में। जहां अवांछित तत्वों (समुद्री डाकू, आतंकवादी और उग्रवादी गुटों का मुफीद प्रशिक्षण स्थल) की सक्रियता जगजाहिर है। इस समुद्री रास्ते से पेट्रोल–डीजल की तस्करी पहले भी होती रही है। पेट्रोल और डीजल के साथ इस बार इस रास्ते से लगभग 2 दर्जन आतंकी भी प्रवेश पा गए। चूंकि भारत के समुद्री मार्ग की सुरक्षा पूरी तरह राम भरोसे है। समुद्र में कोई जहाज घूम रहा होता है तो इसकी जानकारी तट रक्षक के पास नहीं होती है। यहां तटरक्षक डीजी शिपिंग की देखरेख में काम करते हैं। डीजी शिपिंग सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त सुचनाएं तटरक्षकों के साथ नहीं बांटता। डीजी शिपिंग जो जानकारी देते हैं, वह सुरक्षा के लिहाज से डीजी शिपिंग सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त सुचनाएं तटरक्षकों के साथ नहीं बांटता। डीजी शिपिंग जो जानकारी देते हैं, वह सुरक्षा के लिहाज से डीजी शिपिंग सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त सुचनाएं तटरक्षकों के साथ नहीं बांटता। डीजी शिपिंग जो जानकारी देते हैं, वह सुरक्षा के लिहाज से डीजी शिपिंग सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त सुचनाएं तटरक्षकों के साथ नहीं बांटता। डीजी शिपिंग जो जानकारी देते हैं, वह सुरक्षा के लिहाज से डीजी शिपिंग सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त सुचनाएं तटरक्षकों के साथ नहीं बांटता। डीजी शिपिंग जो जानकारी देते हैं, वह सुरक्षा के लिहाज से उसका अधिक महत्व नहीं होता है। जबकि पूरी दुनिया में यह नियम है कि तट रक्षक को सूचित किए बगैर कोई जहाज देश की समुद्री सीमा के अंदर घुस नहीं सकता है। भारत में भी लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि तट रक्षकों के 'अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल' को बदल कर तट रक्षकों को समुद्री सूचनाओं की नोडल एजेंसी बनाई जानी चाहिए।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से मुम्बई जैसी घटनाओं की कीमत आधिकारिक तौर पर 183 देशी–विदेशी नागरिकों की मृत्यु और 216 देशी–विदेशी नागरिकों को घायल होकर चुकानी पड़ी। मृतकों में इजरायल और जर्मनी के तीन–तीन, कनाडा के दो, अमेरिका, इटली, चीन, मॉरीशस, थाइलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान और आस्ट्रेलिया के एक–एक नागरिकों की मृत्यु हुई। आतंकी हमलों के सदमें से भारत उबर भी नहीं पाया था, उस समय फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को इस 'उत्तर आधुनिक इस्लामिक वैश्विक आतंकवाद' के उदाहरण के पीछे एक सुंदर पटकथा नजर आई। और महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को अपने अभिनेता पुत्र रीतेश देशमुख के लिए एक हिट फिल्म। फिर क्या था, तीनों प्राणी अगली फिल्म 'प्लान' करने के लिए 'स्पॉट' पर पहुंच गए। बतौर गृहमंत्री आरआर पाटिल ने इतने बड़े आतंकी हमले को – 'छोटी–मोटी घटना' कहकर छोटा साबित करने की कोशिश की और देशभर में इसके बाद उनकी थू–थू हुई। मराठी अस्मिता के नाम पर पिछले छह महीने से सबसे अधिक उछल–कूद मचाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेनानी पहाड़ी चूहों की तरह मीडिया की नजर से लापता हुए। उनका जोर सिर्फ कमजोर रिक्शे, ठेले वालों और मजदूरों पर ही चलता है। अपनी थू–थू कराने में महाराष्ट्र का कांग्रेसी नेतृत्व ही अव्वल नहीं था, बल्कि केरल के सीपीएम मुख्यमंत्री ने एक शहीद जवान के लिए कह दिया कि 'यदि वह शहीद ना होता तो उसके घर कुत्ता नहीं जाता।' वैसे 'तो' वाली बात अक्सर बड़ी अजीब होती है। एक शहीद के लिए इस तरह के वाक्य उचारने मुख्यमंत्री महोदय से कोई क्यों नहीं पूछता कि यदि वे पैदा ही नहीं हुए होते 'तो' निश्चित तौर पर केरल का मुख्यमंत्री कोई और होता। इस हमले के दौरान राजनीतिक नेतृत्व द्वारा जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान एक के बाद एक कर दिए गए, उसमें यही स्थिति है कि किस–किस को याद करें और किस–किस को भूलिए। धर्मनिरपेक्ष दल के अति धर्मनिरपेक्ष नेता एआर अंतुले को इस पाकिस्तान समर्थित आतंकी कार्यवाही में भी 'हिन्दू आतंकवाद' की गंध मिली। उनके इस सूंघने की अति शक्ति को किसी ने दाद नहीं दी, ऊपर से कई लोगों ने उन्हें सोच–समझ कर बोलने (अर्थात् नाक पर फिल्टर लगाने की) की सलाह जरूर दे दी।

अपनी बातों से यह सभी राजनीतिक बात बहादुर/भाषण बहादुर मुकर सकते थे लेकिन यह इलैक्ट्रानिक मीडिया के बाइट कलेक्टर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। वे अपने बात से मुकरे इससे पहले चैनलों ने लगातार फूटेज दिखानी शुरू कर दी। वैसे चैनलों की बदनामी भी कम नहीं हुई। बताया जाता है कि इन्हीं इलैक्ट्रानिक चैनलों की वजह से आतंकी सेना के साथ 60 घंटे तक मुकाबला करने में सक्षम हुए। बताया यह तक गया कि आतंकियों को मोबाइल पर हिन्दुस्तानी चैनलों के लाइव कार्यक्रम की फीड पाकिस्तान से मिल रही थी।

बहरहाल अब संकट के बादल टल गए हैं, लेकिन अब भारत को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ■

मुलाकात

प्रा. मिलिंद मराठ
(नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभाविप)

प्रा. मिलिंद मराठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। प्रस्तुत है उमाशंकर मिश्र द्वारा उनसे की गई बातचीत के प्रमुख अंश।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष का दायित्व सौंपे जाने पर आपको सर्वप्रथम शुभकामनाओं के साथ बधाई देना चाहूंगा।

धन्यवाद।

अध्यक्ष के तौर आपकी प्राथमिकताएं भविष्य में क्या रहने वाली हैं?

अभविप सदैव संयुक्त नेतृत्व में विश्वास करता है। इसलिए अभविप की जो भी प्राथमिकताएं होती हैं सब मिलकर तय करते हैं। हमारी कुछेक प्राथमिकताएं जैसे बांग्लादेश घुसपैठ के खिलाफ अभियान चलाना, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरों को ध्यान में रखते हुए जनजागृति का प्रचार प्रसार करना, एसी/एसटी छात्रावासों के संबंध में अभाविप द्वारा चलाए गए अभियान को आगे बढ़ाना और शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ आवाज उठाने जाने जैसे विषय आग्रिम सूची में रहेंगे। शिक्षा का व्यावसायीकरण के घातक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण बुद्धिमान लेकिन गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। गरीबी किसी छात्र के पिछड़ने का कारण बन जाए और सरकार मौन बैठी रहे, यह सही नहीं कहा जा सकता।

हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अभाविप के चिकननेक आंदोलन के बारे में बताएं?

देश भर से आए हजारों अभाविप कार्यकर्ता सीमा से 15 किमी. की दूरी पर चिकननेक नामक स्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए थे। साथ ही दो चरणों में देश भर में विश्वविद्यालय बंद का भी आवहान किया गया था। इसमें हमें भारी सफलता मिली। इस अभियान के कारण सरकार के साथ साथ देश भर के नागरिकों में भी बांग्लादेशी घुसपैठ के खतरों की ओर ध्यान एकत्रित हुआ है। इस बात का प्रमाण हाल में विदेश मंत्री के एक बयान से मिलता है, जिसमें उन्होंने भी घुसपैठ के खतरे को स्वीकार किया है। यही नहीं 17 दिसंबर को इस संबंध में संसद में भी प्रश्न पूछे गए। इस तरह से हमारा जो मकसद था कि देश की सुरक्षा के संदर्भ में घुसपैठ की ओर सरकार एवं जनता का ध्यान आकर्शित करना, उसमें हम सफल हुए हैं। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन के साथ हुई है। वह यह कि इस आंदोलन के बाद किशनगंज एवं आसपास के भारतीय लोगों का हौंसला बढ़ गया है। उन लोगों को इस बात का अहसास हुआ है कि अब उन्हें उनके अधिकारों से वंचित होने से बचाने के लिए देश भर के युवा उनके साथ आ खड़े हुए हैं। तो यह एक अच्छी बात कही जा सकती है। दूसरी ओर वोटर्स लिस्ट को लेकर भी विद्यार्थी परिषद् अभियान चला रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि गलत एवं संदिग्ध लोगों के नाम इस सूची में न शामिल होने पाएं। सरकार पर दबाव बना तो यह काम बारीकी से हो पाएगा। वोटर्स लिस्ट की जांच सूक्ष्मता से हो इस बात के लिए हम कृतसंकल्प हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश बार्डर पर बाड़ लगाने का काम भी आरंभ हो रहा है। ऐसी काफी सफलताएं हमें मिल रही हैं।

एन.सी.ई.आर.टी के निदेशक प्रो. कृष्ण कुमार ने हाल ही में मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली को छात्रों के भविष्य के लिए घातक बताया है। आपकी क्या राय है?

उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही है, मुझे नही मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली बुद्धिमत्ता की बजाय याददाश्त पर अधिक केन्द्रित रहती है। यह इसकी सबसे बड़ी खामी है। कुछ संस्थानों मे मौखिक एवं परियोजना कार्य आरंभ किए गए हैं। लेकिन अलग अलग संस्थानों में इनका पृथक स्वरूप देखने को मिलता है। मूल्यांकन की समस्या को देखते हुए वृहद स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है।

देश भर के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की गुणात्मकता के बारे में आपकी क्या राय है। शिक्षा को सर्वसुलभ एवं गुणात्मक बनाए जाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए?

यह एक विडंबना है कि हम अभी शिक्षा को सर्वसुलभ ही नहीं बना पाए हैं, जबकि इसका व्यावसाय किया जाने लगा है। शिक्षा पर सबका अधिकार है, इसलिए जन–जन तक शिक्षा पहुंचाना एवं उसे सर्वसुलभ बनाना आज की जरूरत है। राज्यों एवं केन्द्र सरकार को इसके लिए बड़ी राशि के आवंटन की जरूरत है। दूसरी बात शिक्षा के निजीकरण को रोकने में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भूमिका से जुड़ी है। सरकार को इसके लिए सख़्ती से निपटना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर तीन बातें ध्यान में आती हैं। पहली तो यह कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। दूसरी बात पाठ्यक्रमों की पुर्नरचना से जुड़ी है। पाठ्यक्रम पुराने हो चुके है, उसमें बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। तीसरी एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमें शिक्षा को बेहतर बनाना है तो संसाधनों को भी बेहतर बनाना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त बनाए जाने वाली तमाम चीजों की व्यवस्था सुनिष्चित हो जाए।

वर्तमान केन्द्र सरकार की शिक्षा एवं रोजगार संबंधी नीतियों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

केन्द्र सरकार की नीतियों से अभाविप सहमत नहीं है। इसका एक उदाहरण शिक्षा जैसे बुनियादी विशय का वर्ग विभाजन किया जाना है। शिक्षा में पहली बार अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जा रही है। आखिर अन्य वर्ग के छात्र किसी दूसरे वर्ग के छात्रों से अलग कैसे हो सकते हैं? एबीवीपी इससे खुश नहीं है। इसी तरह से सच्चर कमेटी में मुस्लिम विद्यार्थियों को विशेष सहूलियतें देने की बात भी कही गई। केन्द्र सरकार के ऐसे भेदभावपूर्ण कदमों का अभाविप खंडन करती है। शिक्षा के अलावा वर्तमान केन्द्र सरकार राष्ट्र सुरक्षा जैसे मसले पर भी असफल रही है। अफजल गुरू फांसी दिए जाने का मामला आज तक अटका हुआ है। उसे तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण वर्तमान केन्द्र सरकार ऐसा करने से कतरा रही है। ऐसे आतंकवादी भारत को एक आसान लक्ष्य समझने लगे हैं। यूएनओ की एक रिपोर्ट में भी इसी तरह की बात कही गई है कि भारत आतंकवाद के मसले पर सख्त देश की छवि प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। यह केन्द्र सरकार की विफलता का परिचायक है।

वर्तमान परिवेश में व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? या सब ठीक है?

जिस तेजी से व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है उस तरह से रोजगार युवाओं को नहीं मिल पा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा की गति इतनी जरूरी नहीं है। इसके लिए जिस तेजी के साथ दोयम दर्जे के संस्थान खुल रहे हैं, उससे शिक्षा का व्यावसायीकरण बढ़ा है। बेरोजगारी के साथ साथ ऐसे में गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

यौन शिक्षा की वकालत कितनी सही है?

नाको द्वारा जिस तरह से एड्स को हौव्वा बनाकर यौन शिक्षा की बात को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। विद्यार्थी यदि स्कूल में जाकर यौन शिक्षा ग्रहण करेगा तो भारतीय मूल्यों का क्या होगा। यह तो पश्चिमीकरण का परिचायक है। नाको द्वारा उपभोग संस्कृति को प्रसारित करने का षडयंत्र किया जा रहा है। ऐसे में लैंगिकता का वातावरण फैलेगा। रही बात तो यौन शिक्षा की तो यह तो कुटुम्ब में रहकर मिलती आ रही है। इसके विकल्प हो सकते हैं। समुदाय के स्तर पर भी बात की जा सकती है। लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के कच्चे मन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसे बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता।

सत्यम् के झूठ पर क्या कहेंगे?

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह एक बहुत बड़ा हादसा है। इसमें सत्यम के जिस मुख्य डायरेक्टर राजू की बात इस कुकृत्य में शामिल होने को लेकर की जा रही है, उसके अलावा केन्द्र एवं राज्य सरकार के भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। वित्त विभाग की भी इसमें भागीदारी हो सकती है। उपभोक्ताओं एवं निवेशकों का विश्वास बना रहे इसके लिए ऑडिट संस्थाओं को भी चांज के घेरे में लेना चाहिए। ऑडिट संस्थाओं का चरित्र इस घटना के बाद संदेह के घेरे में आ गया है। इससे निवेशकों एवं उपभोक्ताओं के विश्वास को ठेस पहुंची है। ■

शैक्षिक परिवर्तन : आगामी दिशा एवं योजना

– अतुल कोठारी –

(राष्ट्रीय सहसंयोजक
शिक्षा बचाओ आन्दोलन समिति)

शिक्षा बचाओ आन्दोलन समिति की शुरूआत 2 जुलाई 2004 को हुई। अपने चार वर्षों के अल्पकाल में इसने राष्ट्रीय स्तर पर एक सजग एवं प्रभावी आंदोलन के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आने वाले वर्षों में यह पूरे देश में शिक्षा परिवर्तन के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे – ऐसी अपेक्षा अनेक शिक्षाविद्, शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं आमजन के मन में है।

शुरूआत के दिनों से शिक्षा बचाओ आन्दोलन ने पाठयक्रम सम्बन्धित विकृतियों को उठाया, उनपर विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से संघर्ष किया तथा सफलताएँ प्राप्त की। एन.सी.ई.आर.टी. की इतिहास की पुस्तकों में तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत किए गये तथ्यों एवं आपत्तिजनक अंशो को चिह्नित कर उनपर देशभर में आंदोलन चलाया गया तथा न्यायालय में जीत प्राप्त कि। ठीक इसी प्रकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (इग्नू) के पाठ्यपुस्तकों में हिन्दू देवी–देवताओं पर लिखे अति आपत्तिजनक अंशो पर संघर्ष कर सरकार को उन्हें वापस लेने पर बाध्य किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री को आठ दिनों के अंदर संसद में इस सम्बन्ध में घोषणा करनी पड़ी। केन्द्र सरकार द्वारा यौन शिक्षा को विकृत रूप में लागू करने के प्रयास पर देश भर में जनजागरण एवं आन्दोलन चलाया गया फलतः ग्यारह राज्यों की सरकारों ने यौन शिक्षा को इस रूप में लागू करने से स्पष्ट मना कर दिया। केन्द्र सरकार भी इस पर पुनर्विचार करने को मजबुर हुई। राष्ट्रीय खुला विद्यालय के पाठ्यक्रमों में देश के क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहने पर आपत्ति दर्ज की गई। उड़ीसा की पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, भाजपा को सांप्रदायिक संगठन कहने पर आंदोलन किया गया जिससे राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई की।

शिक्षा बचाओ आंदोलन ने शिक्षा क्षेत्र में लोकतांत्रिक माध्यम से उचित परिवर्तन के लिए प्रयास किये है। विभिन्न शैक्षिक विषयों पर आंदोलन कर जन जागरण करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसे हमने अपनाया। अनेक विषयों पर देश के कानून के अंतर्गत न्यायालय में प्रयास किये गये हैं जिसका जिला से लेकर उच्चतम न्यायालय में अनुकुल परिणाम भी आये है। अपने देश के लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करते हुए अनेक ज्वलंत विषयों पर भी हमारी पहल पर संसद एवं विधान सभाओं में प्रश्न उठाये गये तथा चर्चाएँ भी हुई है।

हमारा लक्ष्य विभिन्न विषयों पर धरना, जुलुस, प्रदर्शन एवं नारेबाजी करना ही नहीं है हालाँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अर्न्तगत विभिन्न विषयों पर जनजागरण एवं उचित कार्रवाई हेतु हम इन माध्यमों का सहारा लेते हैं। कई बार परिस्थितियाँ हमें बाध्य करती हैं। राष्ट्रीय खुला विद्यालय के पाठ्य पुस्तकों में देश के क्रांतिकारियों के आतंकवादी कहने पर हमने अधिकारियों से मिलकर अपनी आपत्तियाँ दर्ज की। अधिकारियों ने उचित कारवाई की तब हमने इस विषय के प्रचार का भी मोह नहीं किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम में इतिहास के पुस्तक के संबध में हमने ज्ञापन एवं कानूनी नोटिस देकर दो महीने का समय दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस दिशा में उचित कदम उठाते हुए आवश्यक सुधार किया फलतः हमने किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं किया। लेकिन कभी–2 इससे उलट अनुभव भी आता है जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास की पुस्तक जिसमें हिन्दू देवी–देवताओं को अपमानित किया गया है एवं समाज विज्ञान की पुस्तक में वेदों के गलत उदाहरण देकर महिलाओं को अपमानित करने वाली सामग्री परोसी गई है। इस विशय पर बाध्य होकर हमें आंदोलन करना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के उचित निर्देश के बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस पुस्तक में परोसी गई विकृत सामग्री को हटाने की घोषणा अभी तक नहीं की है।

हमारा लक्ष्य प्रचार प्राप्त करना अथवा इसके लिए आंदोलन करना नहीं है। हम शिक्षा में समाज का सहभाग बढ़े इस हेतु समाज में जागृति लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अभी तक विभिन्न विषयों पर देशभर में 700 संगोष्ठियाँ

आयोजित की गई हैं जिनमें 1.5 लाख से भी अधिक लोगों का सहभाग हुआ है। यौन शिक्षा के विषय पर राज्य सभा की पीटीशन कमिटी को 41,000 ज्ञापन तथा पत्र प्राप्त हुए। अब तक 45 पुस्तिकाओं का प्रकाशन हो चुका है जो देशभर में 6000 लोगों को भेजी जाती हैं। देश के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न भाषाओं में लाखों पत्रक बाँटे गये तथा विभिन्न विषयों पर हस्ताक्षर अभियान चलाए गये हैं। यौन शिक्षा के विषय पर 4,15,000 हस्ताक्षर प्राप्त किये गये जिसमें जैन समाज का बड़ा योगदान रहा। इसी विषय पर आयोजित सम्मेलन में 26 संस्थाएँ साथ में आई। एन.सी.ई.आर.टी की पुस्तक जिसमें लिखा था, 'जाट लुटेरे थे' पर हरियाणा में पुरा जाट समाज आंदोलित हुआ इसका सकारात्मक परिणाम भी हुआ। एन.सी.ई.आर.टी की पाठ्यपुस्तक में भगवान महावीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर जैन समाज के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा अलवर जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई जिसमें न्यायालय का निर्णय अपने अनुकुल आया। इसी तरह आर्य समाज एवं स्वामी दयानन्द सरस्वती के विषय में आर्य समाज के कार्यकर्ता द्वारा चण्डीगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कि जिसका भी सकरात्मक परिणाम प्राप्त हुआ। शिक्षा बचाओ आंदोलन के कारण विभिन्न शैक्षिक विषयों पर अनेक बार देश की संसद एवं विभिन्न राज्यों के विधान सभाओं में भी मामले गुँजे।

हम शिक्षा को देशहित एवं समाजहित में राष्ट्रीय अवधरणा के अनुरुप ढालना चाहते हैं। देश की जनता का भी मन भी इसी प्रकार से है। परिणामस्वरूप देश में 30 से अधिक शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, अध्यात्मिक संस्थाएँ एवं विभिन्न राजनैतिक नेतृत्व का इस आन्दोलन को समर्थन प्राप्त हुआ है। केन्द्र एवं राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में व्याप्त भयानक विकृतियों के कारण भी आंदोलन की आवश्यकता सबने महसूस कि तथा आगे भी इस प्रकार का आंदोलन चलाना पड़ेगा, इस में किसी को संदेह नहीं है।

देश में एक ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें इसकी अत्याधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हमारी "शिक्षा कैसी हो" –समाज इस पर चर्चा करे तथा स्पष्ट मानदण्ड निर्धारित करे। यह कार्य स्वतंत्रता के पश्चात तुरन्त शुरू हो जाना चाहिए था परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया। सरकार ने कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, राधकृष्णन आयोग, 1986 की शिक्षा नीति आदि आयोग बनाऐ जरूर, इनके द्वारा अच्छे सुझाव भी आये परन्तु राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इनका क्रियान्वयन नही हो पाया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन शिक्षा क्षेत्रा में आमूल चुल परिवर्तन लाने तथा समाज के समक्ष एक नया विकल्प प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कार्य आवश्यक लगते है :–

– शिक्षा के क्षेत्र में देशव्यापी जनजागरण।

– शिक्षा का हित चाहने वाले शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्यक्ष छात्रा, शिक्षक, शिक्षाविद शिक्षा को संचालित करने वाले विभिन्न संस्थानों के संचालक मंडल, सरकारी अधिकारी तथा ऐसे लोगों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित कर, सक्रिय एवं संगठित करके उन सभी के सहयोग से शिक्षा में एक नए विकल्प की तैयारी शुरूँ करना।

ये प्रयास विकेन्द्रित एवं देशव्यापी होना आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न विश्व विद्यालयों, संस्थानों, सामाजिक संगठनों द्वारा शिक्षा के पाठ्यक्रम व्यवस्था प्रद्धति एवं नीति आदि के लिए नए मानदण्डों एवं विकल्प तैयार करने का प्रयास करना होगा। इस हेतु सेमिनार, संविमर्श, संगाष्ठी, परिचर्चा परिसंवाद आदि आयोजित करना तथा पाठ्य–पुस्तक एवं साहित्य तैयार करने का कार्य हमारी प्राथमिकता होगी। इस प्रयासो के द्वारा तैयार की गई पुस्तकें दिशा निर्देश, देश के सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों जैसे निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न सरकारें इसको स्वीकार कर करे – इसके लिए प्रयास करना होगा। इन सभी प्रयासों में देशभर के शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठन भारतीय चिंतन के आधार पर प्रत्यक्ष कार्य करने वाली सामाजिक–आध्यात्मिक–धार्मिक संस्थाएँ, शिक्षा का हित चाहने वाले विभिन्न प्रकार के व्यवसायी एवं राजनीतिक नेतृत्व का सहयोग प्रमुख रूप से अनिवार्य है।

इन सारे प्रयासो के माध्यम से देश की शिक्षा की विकृतियाँ एवं गलत बातो को दूर किया जाएगा। देशव्यापी जनजागरण के साथ–साथ देश के परंपरागत ज्ञान–विज्ञान को आधुनिक संदर्भ में परिभाषित कर देश की शिक्षा की पाश्चात्य प्रभावों से मुक्त कर भारतीय संस्कृति के अनुरूप करना होगा। शिक्षा में विकल्प की तैयारी के साथ–साथ भारतीय भाषाओं को पुनः स्थापित करने का कार्य भी अति आवश्यक हैं। पूर्व राष्ट्र प्रमुख डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 2020 की विकसित भारत की कल्पना या राष्ट्र के पुन निर्माण द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरू स्थान पर स्थापित करने का संकल्प शिक्षा के माध्यम से ही भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(लेखक शिक्षा बचाओ आन्दोलन के राष्ट्रीय सह–संयोजक तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय के सह–सचिव हैं)

परिचर्चा

पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर अमेरिका हमला कर सकता है तो भारत क्यों नहीं ?

रिचा

प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बार सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। अमेरिका आज यदि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है तो इसके पीछे आतंकवाद का वह डर छिपा हुआ है, जिसकी भयावहता को विश्व का सबसे ताकतवर देश होने के बावजूद अमेरिका झेल चुका है।

आतंकवाद का ऐसा वीभत्स रूप देखने के पश्चात् अमेरिका को इसके खिलाफ आवाज उठाने की याद आई है। वरना यही वह अमेरिका था जिसको दक्षिण ऐशियाई देशों में भारत का एक सशक्त देश के तौर पर उभरना हमेशा खलता था। इसी के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके कुकृत्यों को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन जब पासा पलटा और आतंकी हमला अमेरिका पर भी हो गया तो मजबूरन अमेरिका ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर बमबारी आरंभ कर दी है।

लेकिन यहां भारत कसाब जैसे आतंकी के पाकिस्तानी होने का सबूत पूरी दुनिया के सामने रख चुका है। फिर भी पाकिस्तान इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे क्या इस बात की क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह की बमबारी की छूठ अमेरिका को पाकिस्तान की ओर से दी जा रही है, क्या ऐसा भारत के संबंध में भी पाकिस्तान रूख अपनाएगा? निश्चित तौर पर नहीं। पाकिस्तान एक धूर्त सियार की तरह है जो खुद को सिंह बताता है। भारत की ओर से बममारी किए जाने पर पाकिस्तान वैश्विक बिरादरी के समक्ष भारत को गलत ठहराने लगेगा।

और खुद अमेरिका जो आतंकवाद पर भारत का साथ देने की बात करता उसके माथे पर भी शिकन की लकीरें छा जाएंगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि दो देशों के बीच संबंधों को कूटनीतिक तौर पर देखते हुए हल किए जाने की जरूरत है।

मयूरा गुप्ता

जहां तक मेरा मानना है कि आज मुंह तोड़ जवाब देने का ही जमाना है। कब तक हम महात्मा गांधी जी के विचारों को मानते हुए अन्याय को सहते रहेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा जब कोई आपके एक गाल पर चांटा मारे और आप दूसरा भी आगे कर दें। यकीनन अमेरिका की तरह ही प्रत्येक देश को मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। तभी सामने वाला हमारे देश के खिलाफ कुछ करने से पहले डरेगा। जहां तक मेरा मानना है कि भारत के लोग कुछ ज्यादा ही भावुक होते हैं। कभी कभी भावुकता हमारी कमजोरी बन जाती है और अपने दुश्मनों के प्रति भी हम लचीला रूख अपना बैठते हैं। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के मामले में भी हुआ है।

कामिनी

मुझे नहीं लगता कि बात–बात पर युद्ध करना किसी भी देश के लिए एक अच्छा है। एक युद्ध से कितनी तबाही होती है इस बात का अंदाजा शायद हम लोग नहीं लगा सकते। यह तो ईरान और ईराक के लोग ही बता सकते हैं, जिन्होंने इसकी विभीषिका को झेला है। यदि किसी बात का हल आपस में बैठ कर निकाला जा सकता है तो युद्ध की क्या जरूरत? युद्ध तो सबसे आखिरी हल होता है।

गीता

कोई भी देश लड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन जब अन्य देश उस देश को नजायज सता रहा है तो कोई कब तक चुप बैठा जा सकता है। भारत ही है जो इतने आतंकी हमले होने के बाद भी अब तक चुप बैठा है। लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकती कि यह पूरी तरह से गलत है। हो सकता है कि अपने देश की इसी में भलाई हो।

राष्ट्र निर्माण में आगे आएं

सूचना प्रौद्योगिकी छात्रों से सरकार्यवाह श्री मोहनराव भागवत का आह्वान

गत 4 जनवरी को नई दिल्ली स्थित मावलंकर सभागार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक और उपलब्धि का साक्षी बना। इस दिन यहां सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन से जुड़े युवाओं को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का विषय था 'हम युवा का राष्ट्र निर्माण में योगदान।' इसके मुख्य वक्ता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री मोहनराव भागवत।

श्री मोहनराव भागवत

अपने उद्‌बोधन में श्री मोहनराव भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम का प्रारंभ ही राष्ट्र शब्द से हुआ है, इसलिए राष्ट्र निर्माण से जुड़े हर कार्य से उसका संबंध है। संघ मानता है कि राष्ट्र निर्माण का कार्य सिर्फ एक सरकार या कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं कर सकता है। इसके लिए पूरे समाज की भागीदारी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के कीर्तिवर्धन में सामान्य व्यक्ति का बड़ा योगदान होता है। इसलिए जब सामान्य आदमी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तब राष्ट्र निर्माण में बाधा आती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो उसे निर्माण कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी गुण–सम्पदा को धारण करने वाले लोग युवा होते हैं।

युवा होने में उम्र कोई बाधा नहीं है, बल्कि मन बाधक है। यदि 60 साल का व्यक्ति भी समाज जीवन में पूरी तरह सक्रिय है, निर्माण कार्य में लगा है, तो वह युवा कहलाएगा। किन्तु कोई 25 साल का नौजवान मन से थक गया है, निष्क्रिय है तो वह युवा नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा कि युवा जिद्दी होता है। वह जो तय करता है उसे पूरा अवश्य करता है। युवा सकारात्मक सोचता है। इस कारण वह विभिन्न बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ता है, अपना कार्य करता है। इसलिए देश के विकास में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

उन्होंने कहा कि जब देश का भाग्य बदलता है तब देश का व्यक्ति सुखी होता है। इसलिए हमें अपने देश का भाग्य बदलने में योगदान देना चाहिए। जब हम अपने शरीर, मन, बुद्धि को सन्तुलन में रखकर सबके विकास की बात करेंगे, सबको आगे बढ़ने का अवसर देंगे तभी देश विकास करेगा। श्री भागवत ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने से पहले हमें अपने आपको पहचानना होगा, हम क्या हैं? उन्होंने सर्कस के सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या हम किसी 'रिंग मास्टर' के इशारे पर नाचेंगे या अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ेंगे? आज के युवा को अपने कार्यों को करते हुए यह ध्यान रखना होगा कि उसके देश को कोई रिंग मास्टर हांकने की चेष्टा तो नहीं कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने राष्ट्र की प्रकृति समझकर अपनी बुद्धि, धन और समय का सदुपयोग करें। ऐसा करने से हम अपने इसी जन्म में भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर पाएंगे।

समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर क्षेत्र के संघचालक डा. बजरंग लाल गुप्त, क्षेत्रीय प्रचारक श्री रामेश्वर, प्रान्त संघचालक श्री रमेश प्रकाश, प्रान्त प्रचारक श्री प्रेम कुमार सहित लगभग 1000 युवा उपस्थित थे।

India offers great opportunity

Dr Bharat Jhunjhunwala

The present global crisis can be looked at in two ways. The mainstream approach is that this is a truly 'global' crisis and all countries will sink or sail together through it. This writer's view, on the other hand, is that we will be affected less than others and in the end this will see us emerge as winners. This is so because our economy is less integrated with the world, thanks to opposition to blind globalisation by Swadeshi Jagaran Manch and others. We are largely self-dependent for both generation of income and meeting our needs of clothes, housing and food. This relative self-sufficiency will insulate us from the ill effects of global crisis and enable us to stand firm while others sink.

The immediate impact of the global crisis on our share markets will certainly be negative as seen in the crash of Sensex. The global inflow of capital which had raised the Sensex to 21k has reversed and so also fortunes of our share markets. The question to consider is whether this negative impact will be of short—or long duration? This writer reckons this will be short-term impact. Only so much capital can go back which has come in earlier. This outflow cannot be unlimited or unending. FIIs have already started coming back. There has been a net inflow of FII funds in December 2008. his is seen in the Sensex rising from 8K to around 10k presently.

This inflow may soon turn big. The outflow in the last quarter was due to panic among western banks. They wanted to bring back their capital to safety of their own economies. This panic has eased now. The global investor is once again start looking for investment opportunity. The dollar is likely to decline in the coming times because the US economy has lost its basic competitive edge. The decline of dollar will encourage American banks to look for a safe haven outside their borders. India can provide precisely such an opportunity. Our growth rate at about 7 per cent is still reasonably good. Inflation has come down to single digits. This strength of ours is likely to persist because we have less connection with the global economy in comparison to other major economies of the world, including China. The relative stability of the Indian economy will soon become visible and global investors may turn in this direction.

There is another reason for us not being hit by outflow of capital. The Global Development Finance report of the World Bank tells us that developing countries as a group have become net exporters of capital in the last five years or so. They have sent huge amounts of capital to the developed countries for building forex reserves.

India has sent about $200 billion in the last five years. We have got only about one-half this amount as foreign investment. This one-half amount will be reduced to, say, one-fourth.

But, simultaneously, we will not be sending huge amounts for building our forex reserves which have declined from $300 to $250 billion presently. Previously we were sending large amount of our wealth to the western countries and getting a part of the same back in the form of foreign investment. Presently, we are bringing back a part of this our wealth which we had sent abroad and we are loosing a larger part of the foreign investment. The immediate loss to us from repatriation of foreign investment is more than the gain from bringing back our forex reserves hence the rupee is declining. But this will reverse soon. Repatriation of foreign capital will soon turn into an inflow. We also need no longer accumulate large forex reserves since the 'hot money' danger is less. The rupee, therefore, is likely to rise again. It has already gained about Rs 3 since the low of Rs 50 to a dollar.

The second channel through which global meltdown transmits to India is that of trade. We export Basmati rice, garments and software largely to the developed countries. These exports will falter as a result of their economies coming under stress and our exports will be hit. This loss is undisputed. However, we do not only export goods to these countries, we also import goods from them. According to World Bank data we exported goods worth 21 per cent of our GDP in 2005 while we imported goods worth 24 per cent. The decline in prices will affect our exports and imports equally. Thus, we stand to gain more from cheaper imports. For example, the loss to our farmers from lower price of Basmati rice will be more than made up by lower price of phosphate fertilizers. The problem is that loss from imports is immediately visible and hyped up while the gain from imports is kept under the wraps. It is like the salaried employee griping about increase in price of pulses while forgetting that his dearness allowance has increased much more in the same period. Thus the global meltdown will not be a loss proposition for our whole economy even though the export sector will be hit.

I am optimist about the overall impact of the global meltdown on the Indian economy. Creation of a global market means that the price of goods will be same across the world. This applies to wages as well. Globalisation now involves greater global equalisation of wage rates. The reduction in freight rates due to improvement in transport technologies has reduced the wage differential between countries. The existing wage rate for unskilled worker in the United States is about $100 or Rs 5,000 per day. It is Rs 200 per day in India. The two are moving towards one common level. This means the wages in the US will decline while those in India will increase. The decline in US wages will be steep while the increase in Indian wages will be relatively small due to our large population. In the result, business activities will move towards India. Basically we will gain while the developed countries will come under stress. This underlying tendency was covered up in the last few decades by continuous development of new pioneering technologies like jet airplanes and internet which made it possible for the developed countries to charge high prices for their new products. Lately the development of such technologies appears to have reached a plateau and consequently wages in the developed countries are moving south. The only problem is that we are dependent upon America for both capital and exports hence American troubles are affecting us for the present—till the world economy settles in the new paradigm. ■

(Organiser)

औद्योगिक डिजाइनिंग में भविष्य

– प्रीति पाण्डेय –

आज हम जिस समाज का हिस्सा है वहां हर कोई अपने आप को किसी न किसी रूप में प्रतियोगी की दोड़ में शामिल किए हुए है। प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ही आज बड़ी–बड़ी कम्पनी अपने प्रत्येक काम को बडे सलीखे से करती है ताकि वह किसी कमी के कारण पीछे न रह जाए।

पहले और अब के बिजनेस में चुंकि जमीन आसमान का फर्क है। आज जब उद्योग एक जैसी कीमत और एक जैसे काम के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो ऐसे हालात में उद्योगों के डिजाइन का ही अंतर पाया जाता है। और देखा जाए तो यही अंतर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रतियोगी कम्पनियों की तुलना में अपनी कम्पनी के उत्पाद सबसे बेहतर करना ही आज प्रत्येक औद्योगिक कम्पनी का उद्देश्य है। इसके लिए उसे औद्योगिक डिजाइनर की आवश्यकता पड़ती ही है।

क्या है औद्योगिकी डिजाइनिंग?

आजकल लोग ग्राहक या उपभोक्ता के रूप में उत्पादों के प्रति अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए किसी भी वस्तु की मांग करते हैं। हालांकि सीमित मात्रा में पूर्णतः नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं , फिर भी औद्योगिक डिजाइनिंग का मुख्य कार्य व्यावहारिकता व पूरी कुशलता के साथ–साथ उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादों के नए डिजाइन तैयार करना है।

नए पैकेट में चीज पुरानी पेश की जाती हैं। यहीं पर औद्योगिक या उत्पाद डिजाइनर के अच्छे अनुभव और उसके विशेष कौशल की परख की जाती है। औद्योगिक डिजाइनर सृजनात्मक रिसर्च पर आधारित एक ऐसी कला है, जो उपभेक्ता दृष्टि से टिकाऊ एंव व्यापक स्तर पर उत्पादों या व्यावसायिक और औद्योगिक प्रयोग के लिए उपकरण तैयार करने के कार्य से जुडी है।

औद्योगिक डिजाइनर के कार्य क्या हैं?

औद्योगिक डिजाइनर के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्पाद की कीमत घटाना होता है। औद्योगिक डिजाइनर सबसे पहले उत्पाद की रूपरेखा तैयार करता है। वह आवश्यक सामग्री की सूची बनाता है, विनिमार्ण का स्थल तथा तरीका तय करता है, जिससे सुरक्षित तथा प्रयोग की दृष्टि से सुविधाजनक उत्पाद तैयार किया जा सके।

इसके बाद उत्पाद को एक आकर्षक रूप देने की तैयारी की जाती है। आरेख और मॉडल बनाए जाते हैं। आखिर में कार्यकारी मॉडल तैयार किया जाता है।

औद्योगिक डिजाइनर को आप सजृनात्मक इंजीनियर भी कह सकते हैं। यह डिजाइनर कला से सम्बंधित हुनर या कौशल इस्तेमाल करता है , ताकि इस प्रकार से आकर्षक व लुभावने उत्पादों को बढ़ावा मिले। औद्योगिक डिजाइनर का काम केवल वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित ही नहीं होता बल्कि उन्हें

आराम, सौन्दर्य–बोध, सुरक्षा, तथा किफायत की दृष्टि से उपभोक्ता की आवश्यकताओं का ध्यान रखना भी होता है चूंकि यह सभी पहलू उत्पाद की बिक्री से सीधे–सीधे जुड़े होते हैं। इनकी वजह से अधिकांश विनिर्माण संबंधी उद्योगों में ' डिजाइन विभाग' बनाना जरूरी हो गया है।

आज ज्यादातर कम्पनियां पूरी तरह से अपने काम में परफैक्ट औद्योगिक डिजाइनर की तलाश में रहती हैं। जिसके दिमाग में क्रिएटीविटी कूट–कूट कर भरी हो।

क्या आवश्यकताएं और योग्ताएं हैं?

औद्योगिक डिजाइन की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि उसमे क्रिएटीविटी होनी चाहिए, कल्पना–शक्ति, सोचने का ढंग काफी तार्किक होना चाहिए अपनी बातों को आरेख बनाकर समझाना आना चाहिए साथ ही उसे उद्योगो की टैक्नीकल नॉलेज होना भी काफी जरूरी है

आईआईटी मुम्बई और दिल्ली में औद्योगिक डिजाइन में दो वर्ष का मास्टर प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें चार सेमेस्टर होते हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतक योग्यता इंजीनियरिंग या वास्तुशिल्प में स्नातक डिग्री है। इस पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए अकादमिक योग्यता के साथ–साथ प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार भी लिए जाते हैं।

संस्थानः–

इंडसट्रियल डिजाइन सैन्टर

इंडियन इंसटिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी मुम्बई
www.idc.iitb.ac.in
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद
www.nid.edu
इंडियन इंसटिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, दिल्ली
www.iitd.ac.in
इंडियन इंसटिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कानपुर
www.iitk.ac.in
डिपार्टमैंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, दिल्ली
www.spa.ernet.in

फीस:–

इस पाठ्यक्रम की फीस लगभग 10,000 रूपये प्रति सेमेस्टर है।

रोजगार के अवसर:–

औद्योगिक डिजाइनर अपनी कंसलटैंसी खोल सकता है। स्वतंत्र औद्योगिक डिजाइनर के रूप में भी काफी अच्छा ऑपशन है।

एक औद्योगिक डिजाइन अपनी डिग्री प्राप्त कर इस विषय की शिक्षा भी प्रदान कर सकता है।

वह किसी कम्पनी में भी औद्योगिक डिजाइनर के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन कर सकता है।

वेतन:–

शुरूआत में वेतन दस हजार रूपए तथा इससे अधिक भी मिल सकता है। लेकिन एक बार सैट होकर अनुभव प्राप्त कर आप आराम से 20–25 हजार रूपये महिने कमा सकते हैं। और बाकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है। आप कहीं जॉब करते करते भी अपनी खुद की कंसलटैंसी चला सकते हैं और साइड बाइ साइड और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ■

(साभार : सहारा)

OBITUARY

Shri Ved Prakash Goyal

Veteran BJP leader Shri Ved Prakash Goyal passed away at the Hinduja Hospital of Mumbai on December 17 following protracted illness. He was cremated in Mumbai the next day.

VP Goyal had been ailing since May this year. He was hospitalised once for a fortnight in May and again for over the past one week. Born on January 31, 1926 at Karnal in Haryana, VP Goyal was educated at Dayanand Anglo Vedic College, Lahore, and did his B.Sc. in Chemical Engineering. He was the Minister of Shipping for two-and-a-half years in the previous Vajpayee-led NDA Cabinet at the Centre.

A former All India treasurer of the BJP, VP Goyal was the party's Mumbai unit president.He became a full-time RSS worker after completing B.Sc. in 1949. Subsequently, he was closely associated with Bharatiya Jana Sangh, Janata Party and the BJP.

He held several positions in his public life like Chairman of House Committee, Rajya Sabha, Chairman of Committee to Discuss Amendments to the Benaras Hindu University Act, 1915, all India treasurer of BJP, Convenor of Overseas Friends of BJP, Member of Standing Committee on Transport and Tourism etc.

Punjab

ABVP Launches Cleaning Drive In Punjab University

Chandigarh: With an aim to give the Panjab University campus freedom from garbage, a cleanliness drive was organized by the ABVP in the campus.

Around 40 boys and girls joined hands to keep the campus garbage-free. Launching the drive, the ABVP activists picked up garbage from the Student Centre and various departments of the varsity.

Speaking on the occasion, Dinesh Chauhan, ABVP, said that students should make all efforts to keep the campus clean. With this endeavour, many activists thanked those who were helping out in the cleaning spree and gave flowers as a mark of appreciation.

"Our aim is to sensitise students about hygiene and everybody should participate in maintaining the campus as well as the city, said Dinesh. ABVP has decided to hold a cleanliness drive every month."

Karnataka

ABVP Urges Comprehensive Policy For CET

ABVP has urged for a comprehensive policy regarding Common Entrance Test (CET).

Addressing media persons , ABVP State Secretary Ravichandra P M said the dialogue between the government and the Comed-K, that takes place every year, has become a trade.

The act of 'filling potholes' instead of providing permanent solutions has continued this year too, he criticised.

"Students are subjected to injustice this year by allotting more seats to Comed-K. The government should put an end to this 'trade agreement' by implementing an Act on the basis of the Supreme Court's order," he said.

It is not right to give 5 per cent seats in Engineering to private people. The decision should be reconsidered and the 55:45 proportion should be continued. Otherwise, students from poor economic background but talented ones will experience injustice, Mr Ravichandra observed.

The government should fix 50:50 seat matrix in Medical category too. The fee, Rs 15,000, should be fixed to 55 per cent of students in Engineering, he urged the government.

The Common Entrance Test conducted by private people should be stopped. Government should make way for a single system. A supervision committee should be constituted to keep an eye on the fee policy and seat sharing, he said.

ABVP welcomes the government decision of reducing the fee of 25 per cent Engineering candidates by Rs 10,000, counselling in three places and conducting CET in two days, he said.

ABVP Protests Death of Student: Demands Dismissal of St Agnes College HOD

Mangalore: ABVP staged a protest in front of the college, demanding suspension of the head of the department of business management of the college, alleging that she was responsible for the death of a student of the college who committed suicide in the college hostel recently.

Ramya, a student of the college, had committed suicide recently because of the harassment of Namrutha Suvarna, who is the head of the department in BBM section of the

college. Ramya was studying in the first year BBM. She had committed suicide at the college hostel by hanging herself.

ABVP also alleged that the college administration is trying to protect the accused and planning to allow her to continue in the same post. The students boycotted classes and came out from their classes in the morning and joined the protesters in front of the college premises.

ABVP urged the principal to take action against the accused within two days, threatening to resume the protest with the support of students from other colleges. Following the assurance of the principal that a decision would be taken at the earliest, the protesters dispersed.

Jammu & Kashmir

Open Choice - Students Demonstrate, Block Tawi Bridge

Jammu : Unfazed by police lathicharge and prevailing cold weather conditions, the students of different city colleges, under the banner of ABVP, continued their stir for "open choice" on seventh consecutive day and took out a massive protest rally.

The students of MAM College boycotted their classes and took out a rally, which marched through Bikram Chowk while proceeding towards GGM Science College.

Enroute, the students, massive in strength, staged demonstration on Tawi bridge due to which vehicular movement remained disrupted for over half an hour. They also held demonstration at Jewel Chowk causing disruption to traffic movement for a brief period.

Later, students of GGM Science College and SPMR College of Commerce also boycotted their classes and joined their counterparts from MAM College.

Addressing the protesting students, ABVP state secretary Suresh Ajay Magotra, who is leading the stir, lambasted the Jammu University authorities for maintaining silence over the genuine demand of the college students and said that if demand is not conceded, students from all the colleges will jump into the struggle.

Only 30 percent of the syllabus has been completed so far, and it's highly unlikely to cover the remaining syllabus within the left over period and demanded immediate grant of open choice.

Meanwhile, Suresh Magotra told that the students of GDC Bishnah also observed complete boycott of classes . The students of Degree College Udhampur also took out a rally in support of "open choice" and blocked the national highway in protest.

Gujarat

HC Notices To Law Colleges on Senate Polls

Ahmadabad : Intervening on the issue of Gujarat University's Senate elections, Gujarat high court on Tuesday issued notices to five law colleges asking them to explain why they have not submitted their voters' list to authorities.

Acting on a petition filed by ABVP member, Samar Desai, Justice MS Shah and Justice HN Devani asked LA Shah Law College, IM Nanavati Law College and MN Law College in the city as well as Government Law College, Khokhra and Somawala Law College in Nadiad to gave a reply.The court has also permitted the petitioner to add other colleges which have not submitted the voters' list.Desai, a student of IM Nanavati Law College, has filed the petition seeking court's direction to university authorities and concerned colleges to complete the voters' list, particularly for its Law faculty.

Ninth annual convention of ABVP in Dehradun

Ninth state annual convention of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) was held in Dehradun on November 10. Representatives from all over the state participated in the convention. Speaking on the occasion ABVP national organising secretary Shri Sunil Ambekar said the whole nation has to fight against Bangladeshi infiltrators and the ABVP would stage a massive demonstration against it on December 17 at Chicken Neck. Acharya Balkrishan of Patanjali Yoga Peeth, Haridwar, said the ABVP did a wonderful job by inculcating the patriotic spirit among the students and it should continue to perform this task in future too as the protection of cultural values is need of the hour. RSS National Executive Member Shri Ram Madhav, senior ABVP leader Shri Ramesh Pappa and many other senior leaders also addressed the delegates. Shri Umed Negi was elected new state president of ABVP while Shri Ramesh Gadiya was elected general secretary.

ABVP condemns terror attack on Mumbai

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) denounced the preplanned attacks at CST station, Taj Hotel, Oberoi Hotel and some other places in Mumbai on November 26. During this entire scene, the ABVP really adored the courage shown by the police force, ATS and the army. "Nation really bows down to the martyrs who died in collision with terrorists. We salute ATS chief Hemant Karakare, Ashok Kamate, Vijay Salaskar and all other police officers who put their lives on fire and at the same time have sympathy for the citizens died in this attack," said ABVP general secretary Shri Suresh Bhatt in a statement issued from Mumbai.

He described the terror attack as the result of Central Government's negligence of security concerns of the nation. "Central government should learn a lesson from this utter chaotic situation and take strong steps against the menace of terrorism. The Government should treat this attack as a War on our Nation and draw strategic plans to wipe this terrorism off from the country. These continuous attacks have proved the incompetence of the Home Minister Shivaraj Patil. We appeal to the people of the nation to pressurise the Government by all democratic ways for getting justice," the statement said.

International Seminar on Global Terrorism by WOSY February 14-15, Bangalore

The world in 21st century is affected severely by globle unrest in the name of terrorism. The terror in the world has crossed the natrional boundaries and has taken an internationalazied structure. Invariably most of the nations across the world are affected by the terrorist attacks. At this point in time it is important for the youth in the world to think and be united against the ill effect of the terrorist activities,without which globle peace and the civilization harmony are not even a distant reality.

Considering the globle importance of the issues of terrorism and its manifestation in terms of cultural disintegration,separatist voice,loss of security for the life,morbidity and mortality coupled with threats on globle economy,WOSY has planned a two day international seminar on "Globle Terrorism".This seminar will be held at Bangalore on 14th and 15th of february 2009.

Quotes by Swami Vivekananda

- Choose the highest ideal and live your life upto that.
- The ideal of the man is to see God in everything.
- Everyone should know that there is no salvation except through the conquering of desires.
- Death being so certain, it is better to die for a good cause.
- Your country requires heroes, be heroes!
- Each soul is potentially divine.
- Work, work, work - let this be your motto.
- Be a hero. Always say, "I have no fear".
- Struggle hard to get money, but don't get attached to it.
- Feel that you are great and you become great.
- At my will mountains will crumble up. Have that sort of energy, that sort of will; work hard, and you will reach the goal.
- Never talk about the faults of others, no matter how bad they may be. Nothing is ever gained by that.
- Let us go forward and do yet greater things.
- The more selfish a man, the more immoral he is.
- Give to the weak, for there all the gift is needed.
- Knowledge exists, man only discovers it.
- Be not afraid of anything. You will do marvellous work.

When I Asked God for Strength
He Gave Me Difficult Situations to Face
When I Asked God for Brain & Brown
He Gave Me Puzzles in Life to Solve
When I Asked God for Happiness
He Showed Me Some Unhappy People
When I Asked God for Wealth
He Showed Me How to Work Hard
When I Asked God for Favors
He Showed Me Opportunities to Work Hard
When I Asked God for Peace
He Showed Me How to Help Others
God Gave Me Nothing I Wanted
He Gave Me Everything I Needed

- Try to love anybody and everybody.
- Go on bravely. Do not expect success in a day or a year.
- Your way is the best for you, but that is no sign that it is the best for others.
- If I am in the dark, let me light a lamp.
- We only get what we deserve. It is a lie when we say, the world is bad and we are good. It can never be so.
- First there should be strict integrity... Secondly, entire devotion to the cause
- You fail only when you do not strive sufficiently to manifest infinite power.
- Whatever you do, devote your whole Mind, Heart, and Soul to it.
- He works best who works without any motive, neither for money, nor for fame, nor for anything else.
- Neither seek nor avoid, take what comes.
- You should work like a master and not as a slave; work incessantly, but do not do a slave's work
- Believe that the soul is immortal, infinite and all powerful.
- Even if the order be wrong, first obey and then contradict it. ■

रैली एवं विशाल सभा
17 दिसम्बर 2008, किशनगंज (बिहार

17 दिसम्बर 2008
किशनगंज
विद्यार्थी परिषद ABVP
घुसपैठ विरोधी आन्दोलन
रैली एवं विशाल सभा
ABV
शक्ति की है ललकार
बचाओ